साप्ताहिक
Live not just breaTHE

# दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 11, अंक : 22 ( प्रति बुधवार ), इन्दौर, 24 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

# कैसे मिट्टी कर सकती है .... जलवायु परिवर्तन से मुकाबला

**मुंबई। पृथ्वी की मिट्टी में मौजूद कार्बन की मात्रा वायुमंडल और सभी पौधों में मौजूद कार्बन से तीन गुना अधिक है। इसका अर्थ यह है कि मिट्टी में कार्बन को समझना और उसे नियंत्रित करना जलवायु परिवर्तन के मुकाबले में बेहद महत्वपूर्ण है। मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीव ( माइक्रोब्स ) मृत पौधों और अन्य जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में कभी-कभी कार्बन सीओ2 के रूप में वायुमंडल में वापस चला जाता है, और कभी-कभी यह मिट्टी में लंबे समय तक सुरक्षित हो जाता है।**

हाल ही में कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब सूक्ष्मजीव मृत पौधों को अपघटित करते हैं, तो मिट्टी में मॉलिक्यूलर विविधता (मॉलिक्यूल की विविधता) पहले बढ़ती है, फिर एक महीने के बाद स्थिर हो जाती है और उसके बाद घटने लगती है। यह शोध नेचर कम्युनिकेशन्स नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या हम मिट्टी से कार्बन का नुकसान कम कर सकते हैं या इसे बढ़ा सकते हैं, जिससे वायुमंडल में सीओ2 नियंत्रित रहेगा। क्योंकि मिट्टी में इतनी बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, छोटी-छोटी बदलाव भी वायुमंडल पर बड़ा असर डाल सकते हैं। दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि मिट्टी में कार्बन मुख्य रूप से ऐसे पौधों से जमा होता है जिनके अवयव कठिन अपघटन वाले होते हैं। लेकिन 2011 में शोधकर्ताओं ने नेचर पत्रिका में एक अहम शोध प्रकाशित किया जिसमें यह सिद्ध हुआ कि यह सच नहीं है। वास्तव में मिट्टी में कार्बन का भंडारण सूक्ष्मजीव, अणु और खनिजों के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करता है। 2020 में शोधकर्ताओं ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मिट्टी में मॉलिक्यूलर विविधता अधिक होने पर अपघटन धीमा होता है, जिससे कार्बन मिट्टी में अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। इसका कारण यह है कि जब विविधता कम होती है, तो सूक्ष्मजीव आसानी से किसी विशेष पदार्थ को तोड़ सकते हैं और सीओ2 को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। लेकिन जब विविधता अधिक होती है, तो अपघटन प्रक्रिया धीमी होती है और खनिजों के पास कार्बन को लंबे समय तक सुरक्षित करने का मौका होता है। इस नए अध्ययन ने पहली बार प्रायोगिक सबूत प्रदान किए कि पौधों का अपघटन मिट्टी में मॉलिक्यूलर विविधता को बढ़ाता है, लेकिन यह वृद्धि केवल पहले महीने तक रहती है। शोध में यह भी पाया गया कि 32वें दिन विविधता अपने चरम पर होती है। इस शोध में एक नई तकनीक का उपयोग किया गया- 18ह भारी पानी। इसमें ऑक्सीजन परमाणु का भारी रूप इस्तेमाल किया गया ताकि सूक्ष्मजीव गतिविधियों का पता लगाया जा सके। पारंपरिक तरीकों में शोधकर्ता कार्बन या नाइट्रोजन के स्तर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस नए तरीके से यह सुनिश्चित होता है कि सूक्ष्मजीव अपनी प्राकृतिक भोजन सामग्री का




उपयोग कर रहे हैं, न कि प्रयोगशाला में दिए गए ग्लूकोज (साधारण शर्करा) का। शोध पत्र में कहा गया है कि इस शोध का अगला कदम यह पता लगाना है कि क्या मिट्टी में अणु, सूक्ष्मजीव और खनिजों की अधिक विविधता वास्तव में अधिक कार्बन भंडारण में मदद करती है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो इसके आधार पर खेती और वन प्रबंधन में नई रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, मिट्टी की संरचना और जैविक विविधता को बढ़ावा देने वाले कृषि और वन्य प्रबंधन उपाय अपनाए जा सकते हैं। शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि इसे लेकर अभी और बहुत कुछ सीखना है, लेकिन यह अध्ययन मिट्टी में कार्बन भंडारण के बड़े रहस्य को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मट्टी केवल पौधों का आधार नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी पहली रक्षा भी है। सूक्ष्मजीव और अणुओं की विविधता मिट्टी में कार्बन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाती है। इस नए शोध से यह स्पष्ट होता है कि मिट्टी की संरचना और जैविक विविधता को बढ़ावा देकर हम वायुमंडल में सीओ2 की मात्रा कम कर सकते हैं और जलवायु संकट से निपट सकते हैं मिट्टी और उसके सूक्ष्मजीवों का सही ढंग से अध्ययन करना और उनका संरक्षण करना अब केवल विज्ञान नहीं, बल्कि भविष्य की स्थिरता के लिए एक जरूरी कदम बन गया है।

## सीएम हेल्पलाइन में अब पानी के साथ अतिक्रमण की शिकायतें बढ़ीं

**इन्दौर। नगर निगम के अधिकारी सीएम हेल्पलाइन एप में दर्ज शिकायतों के निराकरण में गंभीरता नहीं दिखाते हैं जिससे लगातार कुल शिकायतें 3 हजार से अधिक ही चल रही हैं। लेवल 1 में 1400 तो लेवल 3 में 154 शिकायतें पहुंची हैं जबकि पेयजल शाखा की शिकायतें हमेशा की तरह सबसे अधिक हैं जो वर्तमान में 510 हैं वहीं सीवरेज, सिविल, सफाई, अतिक्रमण की शिकायतें भी अधिक हैं।**

आयुक्त दिलीप कुमार यादव को नगर निगम में पदभार संभाले 3 माह हो चुके हैं और उन्होनें अब तक राजस्व, प्रशानिक व्यवस्था, सफाई, जनसुनवाई, रोड निर्माण सहित कुछ अन्य बिंदुओं पर तेजी से काम किया है और सुबह से रात तक फील्ड में दौरा करना, बैठकें लेने के अलावा अधिकारियों को समझाइश के साथ सख्त निर्देश भी काम को लेकर दे रहे हैं। इधर सीएम हेल्पलाइन और मेयर हेल्पलाइन एप में दर्ज शिकायतों में कमी नहीं आ रही है। शहर में सीवरेज, पीने का पानी, सफाई, स्ट्रीट लाईट, अतिक्रमण, कब्जे जैसी समस्याएं अधिक रहती हैं। जनसुनवाई में भी इसी तरह की शिकायतें अधिक आती हैं।

# झाबुआ में जल संरक्षण, सिंचाई और धार्मिक पर्यटन को नई दिशा

**भोपाल महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश शासन किसानों की आय वृद्धि, जल संरक्षण और क्षेत्रीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में जल संसाधन विभाग द्वारा झाबुआ जिले में नवीन जल संसाधन परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे पेटलावद क्षेत्र सहित पूरे जिले के विकास को नई गति मिलेगी।**

सुश्री भूरिया ने बताया कि पेटलावद क्षेत्र में 15.8 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न जल संसाधन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 480 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। स्वीकृत योजनाओं में मुंडत बैराज (लागत 5.99 करोड़ रुपये) से 360 हेक्टेयर तथा मुकामपुरा तालाब नहर रहित योजना (लागत 3.53 करोड़ रुपये) से 120 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि माही नदी पर स्थित श्रृंगेश्वर घाट के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 628.21 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इस परियोजना से नदी तटों का संरक्षण सुनिश्चित होगा तथा धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। श्रृंगेश्वर घाट का विकास क्षेत्र की धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करेगा और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक अवसरों का विस्तार होगा। सुश्री भूरिया ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाएं झाबुआ जिले के किसानों, युवाओं और स्थानीय समुदाय के लिए दीर्घकालीन लाभकारी सिद्ध होंगी तथा जिले की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी।

## मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2030-31 तक निरंतर रखने की स्वीकृति

**भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए 1,782 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया। परियोजनाओं के डूब प्रभावितों के लिए डीपीआर में प्रावधानित 1656 करोड़ 2 लाख रुपये के अतिरिक्त 1,782 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है।**

उल्लेखनीय है कि अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना 5,512 करोड़ 11 लाख रूपये की है। इससे 71 हजार 967 हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा और 125 मेगावाट विदयुत उत्पादन प्रावधानित है। इन तीनों परियोजनाओं से कुल 13 हजार 873 परिवार प्रभावित होंगे, जिन्हें विशेष पैकेज अनुसार निर्धारित मुआवजा प्रति परिवार 12.50 लाख रूपये दिया जायेगा। इसके अलावा 50 हजार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को अतिरिक्त राशि मुआवजा के रूप में देय होगा। मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना में विभाग में 10 लाख या उससे अधिक लागत राशि के कार्य स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। स्वीकृति अनुसार 693 करोड़ 76 लाख रूपये की लागत के लगभग 3810 कार्य पूर्ण किए जा सकेंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व मद में 90 करोड़ 67 लाख रुपये के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई।

# अर्थ नीति ही तय करती है राष्ट्र की प्रगति की दिशा- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

**भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की सशक्त अर्थ नीति और वैचारिक दूरदर्शिता ही उसके विकास की संतुलित गति, स्थायित्व और भविष्य की दिशा तय करती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीता दशक देश की अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम काल रहा है। इस दौरान देश ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों से उबरते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंसङ्क2025 को संबोधित कर रहे थे।**

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। मध्यप्रदेश में निवेश और सरलता से व्यापार-व्यवसाय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार निवेशकों की हर संभव मदद करने को तत्पर है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश करने के इच्छुक हर निवेशक के लिए हमारी सरकार हर घड़ी उनके साथ खड़ी है। निवेशकों की जरूरतों से हम वाक़िफ हैं, इसीलिए जैसी जरूरत, हमारी सरकार निवेशकों की वैसी मदद करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम सब मिल जुलकर %मेक इन इंडिया% और %विकसित भारत% के संकल्प को साकार करेंगे। देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर में 25 दिसंबर को भारतरत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रूपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी को 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' में शामिल होने के लिए ग्वालियर आमंत्रित करते हुए कहा कि यह आयोजन 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' के सफल समापन का साक्षी बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेशकों को बेहतर पॉलिसी, अवसर, इन्सेंटिव, इको सिस्टम, मार्केट लिंकेज और ग्रोथ रेट के साथ-साथ सरकार का फुल सपोर्ट मिलेगा। हमारे यहां उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड और वॉटर बैंक है, यूथ फोर्स है और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी है। उन्होंने निवेशकों से मध्यप्रदेश में निवेश करने के लिए बेहिचक आगे बढ़ने का आहवान किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए भारत की आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक मूल्यों और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस रफ्तार से आर्थिक प्रगति कर रहा है, वह अभूतपूर्व है। सुदृढ़ नीतियों, संरचनात्मक सुधारों, आत्मनिर्भर भारत अभियान और वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास के कारण हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत शीघ्र ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।

देश-विदेश से बड़ी संख्या में आए बिजनेस टायकून्स, उद्योगपतियों, नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, ग्लोबल इकोनॉमी के विचारकों और वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के सभी सदस्यों ने कॉफ्रेंस में शिरकत की। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंसङ्क2025 भारत की आर्थिक सोच, सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक दृष्टि को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है, इससे देश की भावी विकास यात्रा को नई दिशा और ऊर्जा मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कांफ्रेंस में मध्यप्रदेश की बेजोड़ उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य निवेश, उद्योग, कृषि, ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। मध्यप्रदेश में कभी भी औद्योगिक बाधाओं (इंडस्ट्रियल अनरेस्ट) की शिकायत नहीं रही। सरकार की निवेशकों के अनुकूल 18 नई औद्योगिक नीतियों, पारदर्शी शासन-प्रशासन और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण मध्यप्रदेश आज निवेशकों और नव उद्यमियों के लिए एक आकर्षक और भरोसेमंद केंद्र बन गया है। हम निवेशकों को हर जरूरी प्रोत्साहन, न्यूनतम दर पर भूमि, मदद और मार्गदर्शन भी मुहैया करा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इनोवेशन प्रास्पेरिटी एण्ड सेल्फ-रिलायंस = इंडिया पाथ टू ग्लोबल लीडरशिप जैसे विषय पर ऐसे समय में संवाद हो रहा है, जब भारत केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्व को दिशा देने वाली शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। भारतीय परम्परा में अर्थ को कभी भी केवल लाभ तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे लोक कल्याण, संतुलन और दीर्घकालिक समृद्धि से जोड़ा गया है। भारत अब मेक इन इंडिय से लेकर मेक फॉर वर्ल्ड के लिए तैयार है। यह परिवर्तन परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इनोवेशन की नीति से आया है। मध्यप्रदेश भारत के सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में से एक है। हमने ईज़ ऑफ डूइंग को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल पर उतारते हुए उसे स्पीड स्केल और स्किल ऑफ डूइंग में परिवर्तित कर दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने 18 नई औद्योगिक पॉलिसी लॉन्च कीं, जो प्रदेश की ग्रोथ के लिए गेम चेंजर सिद्ध हो रही हैं। धार जिले में देश के पहले और सबसे बड़े पीएम टेक्सटाइल पार्क का भूमि-पूजन किया गया है।

# कभी बाढ़, कभी सूखा- 2064 तक बदल जाएगा मानसून का चरित्र

**नई दिल्ली। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अगर बढ़ते उत्सर्जन को अभी नहीं रोका गया तो 2064, यह वह साल हो सकता है जब मानसून खतरनाक मोड़ ले लेगा। इसकी वजह से एशिया में बारिश और सूखे के चरम दौर सामान्य हो सकते हैं। क्या मानसून, जो सदियों से जीवन का सहारा रहा है, आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दशकों में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आंकड़ों भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही जलवायु के खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही है। ऐसे में चरम मौसमी घटनाओं का आना बेहद सामान्य होता जा रहा है।**

इस बारे में हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में हुए एक नए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने चेताया है कि यदि उत्सर्जन ऐसे ही बढ़ता रहा, तो साल 2064 के बाद एशिया और उष्णकटिबंधीय इलाकों में मौसम का चरम संकट शुरू हो सकता है। अध्ययन से संकेत मिले हैं कि अगले कुछ दशकों में एशिया में बारिश और सूखे के चरम दौर सामान्य हो सकते हैं। मतलब कि यदि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले दशकों में मानसून ऐसा झटका देगा जो जीवन की बुनियाद हिला सकता है। इस अध्ययन के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुए हैं। इस अध्ययन के मुताबिक, एशिया और अन्य उष्णकटिबंधीय इलाकों में हर 30 से 90 दिन के भीतर भारी बारिश और लंबे सूखे का खतरनाक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों इसे 'सब-सीजनल व्हिपलैश' कह रहे हैं, यानी मौसम का ऐसा झटका जो खेती, पानी और ऊर्जा प्रणालियों को बुरी तरह हिला देगा। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे उन्नत जलवायु मॉडलों (सीएमआइपी6) की मदद से मानसून की एक अहम प्रणाली %बोरियल समर इंट्रा-सीजनल ऑस्सिलेशन (बीएसआईएसओ) के व्यवहार का अध्ययन किया। गौरतलब है कि यही प्रणाली गर्मियों में एशियाई मानसून के दौरान 30 से 90 दिनों के भीतर बारिश और सूखे के दौर तय करती है। अध्ययन में यह भी सामने आया कि भविष्य में बीएसआईएसओ के पैटर्न और भी ताकतवर हो जाएंगे, जिससे दक्षिण और पूर्वी एशिया में कहीं भीषण बारिश होगी, तो कहीं लंबे सूखे की मार पड़ेगी। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बारिश लाने वाली एक लहर, जो पहले इंडोनेशिया तक सीमित रहती थी, अब प्रशांत महासागर तक तेजी से फैल सकती है। इसका मतलब है, मानसून से जुड़ी चरम बारिश और सूखे का असर और बड़े इलाके में महसूस होगा।

आशंका है कि उच्च उत्सर्जन की स्थिति में सदी के अंत तक इस बारिश लाने वाली लहर की रफ्तार दोगुनी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि इस बदलाव का असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जोखिम बढ़ेगा। इसकी वजह से ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में बारिश के पैटर्न में बड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है। इतना ही नहीं इसकी वजह से अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से उठने वाली धूल बढ़ सकती है, जिससे अटलांटिक महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित हो सकते हैं। अध्ययन से जुड़ी शोधकर्ता प्रोफेसर मंगकियान लू ने चेताया, सूखे से अचानक बाढ़ में बदलना सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। सबूत बताते हैं कि ऐसे झटकों से वैश्विक धान उत्पादन को होने वाला खतरा, सामान्य बारिश या सूखे की तुलना में 43 फीसदी अधिक है। उनका यह भी कहना है कि एशिया और अफ्रीका के कृषि क्षेत्रों में ऐसे सूखे-से-बाढ़ वाले घटनाक्रम बढ़े, तो दुनिया की खाद्य सुरक्षा गंभीर संकट में पड़ सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन बदलती चुनौतियों से आगे रहने के लिए मौसम और मौसमी पूर्वानुमान प्रणालियों को मज़बूत करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। इसके लिए सरकार और समाज—दोनों को मिलकर अभी से तैयारी करनी होगी। शहरों के ढांचे को जलवायु के झटकों के अनुरूप ढालना होगा, पानी॒ऊर्जा॒ खाद्य प्रणालियों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाना होगा, और जलवायु से जुड़ी बीमारियों की समय रहते पहचान की क्षमता बढ़ानी होगी, तभी आने वाले खतरों का सामना किया जा सकेगा। साथ ही इससे सरकारों और निजी क्षेत्र को दीर्घकालिक योजनाएं बनाने और नीतियां तय करने में सोच-समझकर, सही फैसले लेने की ताकत मिलेगी। अध्ययन का सन्देश स्पष्ट है कि अगर बढ़ता उत्सर्जन अभी नहीं रोका गया, तो आने वाली पीढ़ियों का ऐसे मानसून से सामना होगा, जो जीवन देने के बजाय, जीवन की चुनौतियां बढ़ा देगा।

# भारत की राजधानी दिल्ली आज वायु प्रदूषण के कारण कराह रही

भारत की राजधानी दिल्ली आज वायु प्रदूषण के कारण कराह रही है। इसी के साथ दिल्ली आज केवल राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र नहीं रही, बल्कि देश में बढ़ते पर्यावरणीय संकट का सबसे बड़ा प्रतीक भी बन चुकी है। दुनिया के तीन सबसे अधिक प्रदूषित महानगरों में दिल्ली का शामिल होना किसी एक वर्ष या एक सरकार की विफलता नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही सामूहिक लापरवाही और असंवेदनशीलता का परिणाम है। विडंबना यह है कि दिल्ली में देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाएं, न्यायपालिका और नीति-निर्माण के सभी प्रमुख केंद्र मौजूद हैं, फिर भी प्रदूषण की भयावह स्थिति पर प्रभावी और स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला जा सका है। पिछले कई वर्षों से दिल्ली का प्रदूषण राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय बना रहा है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जिम्मेदार ठहराया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीति करार देते हुए दिल्ली सरकार को कठघरे में खड़ा किया था। इस दौरान मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी संज्ञान लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस और दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सका। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रदूषण जैसी जटिल और बहु-राज्यीय समस्या से निपटने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। केंद्र को चाहिए था कि वह पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कृषि अवशेष जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों और वाहनों से निकलने वाले धुएं पर एक साझा रणनीति तैयार करता। दुर्भाग्य से ऐसे प्रयास या तो आधे-अधूरे रहे या केवल कागजों तक सीमित रह गए। इसी तरह एनजीटी से भी जिस सख्ती और निरंतर निगरानी की अपेक्षा थी, वह देखने को नहीं मिली, परिणामस्वरूप समस्या साल दर साल और गंभीर होती चली गई। आज स्थिति यह है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है, यानी केंद्र, राज्य और नगर निगम, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जो आरोप कभी भाजपा, आम आदमी पार्टी पर लगाती थी, वही सवाल आज भाजपा से पूछे जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इस वर्ष प्रदूषण ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह केवल असुविधा का विषय नहीं रहा, बल्कि सीधे तौर पर जानलेवा बन चुका है। दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा दी जा रही चेतावनियां बेहद गंभीर हैं। अस्पतालों में मरीजों की जांच के दौरान फेफड़ों की स्थिति कोरोना महामारी के समय जैसी पाई जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि यदि संभव हो तो प्रदूषण कम होने तक कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़ दें। किसी भी राजधानी के लिए इससे अधिक शर्मनाक और खतरनाक स्थिति क्या हो सकती है? यह संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के उत्तरी राज्यों के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों की असंवेदनशीलता चिंता पैदा करती है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ देशों ने अपने नागरिकों के लिए दिल्ली यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इससे भारत की वैश्विक छवि को भी गहरा नुकसान पहुंच रहा है। और भी चिंताजनक यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यह कहने को मजबूर हों कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो आम नागरिक खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करता है। जिस दिल्ली में सत्ता, व्यवस्था और संसाधनों का संकेंद्रण है, अगर वहां लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो बाकी देश के हिस्सों का भविष्य क्या होगा, यह सवाल स्वाभाविक है। आज जरूरत है कि केंद्र और राज्य सरकारें राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण को राष्ट्रीय आपात स्थिति की तरह लें। न्यायिक संस्थाओं को भी केवल टिप्पणियों तक सीमित न रहकर प्रभावी निगरानी और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। समय रहते यदि सभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो प्रदूषण केवल हवा को ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य को भी जहरीला बना देगा। यह स्थिति काफी भयावह है। इस हालात से निकलने के लिए सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, तभी समाधान संभव है।

# ओपन थियेटर और जंगल सफारी की चिड़ियाघर देगा सौगात

**इंदौर । चिड़ियाघर में इन दिनों ओपन थिएटर और जंगल सफारी का काम तेजी से चल रहा है। करीब 8 -9 महीने पहले उक्त दोनों प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इसके निर्माण काम पूरा होने के साथ ही निजी हाथों में सौंपने की योजना तैयार की गई है। वैसे दर्शकों का रुझान बढ़े इसके लिए चिड़ियाघर में कई तरह के काम चल रहे हैं।**

बताया जा रहा है कि जंगल सफारी और ओपन थिएटर बनाए जा रहे हैं जिनमें से ओपन थिएटर और जंगल सफारी का काम तेजी से चलने लगा है और संभावना यह है कि अगले साल की शुरुआती 3 से 4 महीने में यह सब तैयार हो जाएगा। हालांकि अन्य कई ऐसे काम भी दर्शकों को लुभाने के लिए यहां पर किए जा रहे हैं ताकि चिड़ियाघर की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ सके। वैसे खासकर छुट्टियों के दिनों में यहाँ अधिक दर्शकों की भीड़ रहती है। इधर जो प्रोजेक्ट दोनों प्रमुख चल रहे हैं उन्हें निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई गई है ताकि इनके रखरखाव के साथ एक निश्चित राशि का टिकट दर भी तय किया जा सके। इसमें आसानी से दर्शक देख सकते हैं एवं ओपन थिएटर में जंगल जैसा नैसर्गिक वातावरण दर्शकों को देखने को मिलेगा। यही कारण है कि यह भी कहा जा रहा है कि चिड़ियाघर में कई देश विदेश के पशु पक्षी होने से भी यहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जंगल सफारी जो वर्चुअल दिखेगा और उसमें ऐसे जानवर भी दिखेंगे जैसे उनके दर्शकों के पास आ रहे हैं। हर जगह खड़े रहने के साथ मूवमेंट भी करेंगे। यह सब ओपन थिएटर में रहेगा जिसमें दर्शकों को वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण सहित जानवरों से जुड़ी फिल्में भी दिखाई जा सकती है। इससे प्राणी संग्रहालय में सालाना इनकम भी बढ़ जाएगी एवं दर्शकों का रुझान भी रहेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं चिड़ियाघर में की जा रही हैं। प्राणी संग्रहालय प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि चिड़ियाघर में नए काम भी कर रहे हैं। प्रदेश के अलावा अन्य राज्य व शहरों से एक्सचेंज ऑफर के तहत जंगली जानवरों को भी यह निरंतर लाया जा रहा है। इससे निरंतर दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ओपन थिएटर और जंगल सफारी से और दर्शक बढ़ेंगे। चिड़ियाघर में निरंतर काम चल रहा है।

**अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2025**

# ऐलोबेरा, महुआ से बने फेसपैक, तुलसी सीरप, आंवला जूस व बेल शर्बत बने सैलानियों की पसंद

**भोपाल अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के छठे दिन सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र ऐलोबेरा , महुआ से बने फेशपैक, तुलसी सीरप, आंवला जूस और बेल शर्बत रहे। सैलानियों ने विंध्य हर्बल एम.एफ.पी. पार्क में बने ग्रोविट, च्यवनप्राश, त्रिफला, अर्जुन, चाय, महुआ फेशपैक और अन्य स्वास्थ्यवर्धक औषधियां भारी मात्रा में खरीदीं। मेले में आयुर्वेदिक चिकित्सकों और पारम्परिक नाड़ी वैद्यों की कार्यशाला का आयो जन किया गया। कार्यशाला में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये पारम्परिक वैद्य शामिल हुये। मेले का समापन 23 दिसंबर मंगलवार को जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार शाम 5 बजे करेंगे।**

समापन की ओर अग्रसर अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के प्रति सैलानियों का उत्साह कम होता नज़र नहीं आ रहा है। सैलानी भारी संख्या में आयुर्वेदिक उत्पाद, नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श और आकर्षक प्रदर्शनियां देखने पहुंच रहे हैं। सोमवार दोपहर तक 1.58 करोड़ रूपये से अधिक की जड़ी-बूटियों और वन उत्पादों की बिक्री हुई। नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श के लिये स्थापित ओ.पी.डी. में आज 120 आयुर्वेदिक चिकित्सकों एवं परंपरागत वैद्यों द्वारा आज 500 से अधिक लोगों को नि:शुल्क परामर्श देकर लाभान्वित किया गया। नि:शुल्क ओ.पी.डी. परामर्श की सुविधा 23 दिसंबर मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे तक संचालित की जायेगी। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में सोमवार को राजधानी भोपाल के विभिन्न आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के विद्यार्थी भारी संख्या में सैलानी के रूप में आये। उन्होंने प्रदर्शनियों को बड़ी तन्मयता से देखा और जिला यूनियनों, प्राथमिक वनोपज समितियों एवं वन धन केन्द्रों के स्टॉल्स पर उपलब्ध जड़ी बूटियों के बारे में भी जानकारी ली। वन मेले में सोमवार को शालेय विद्यार्थियों की इंस्ट्रुमेंटल संगीत की प्रस्तुति, लोक गायन, नुक्कड़ नाटक और आर्केस्ट्रा की प्रस्तुतियां देर शाम तक होती रहीं।

**स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर ( म.प्र. ) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर ( म.प्र. ) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008**